भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4067

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार अनुकूल परिवेश संबंधी अध्ययन

4067. श्री एम. के. राघवनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राज्यों के व्यापार अनुकूल परिवेश के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को उनके व्यापार अनुकूल परिवेश के आधार पर दी गई रैंकिंग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने अपने व्यापार सुगमता सूचकांक को बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वर्ष 2014 से, भारत सरकार पूरे देश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस परिवेश को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के प्रमुख कार्यक्रम के तहत, भारत में व्यावसायिक परिवेश को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबार के लिए अधिक अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने जैसी कई पहलें की हैं, जिसमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास तथा व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। सरकार विनियमन की लागत (सीओआर) संबंधी कार्य भी कर रही है, जिसका उद्देश्य सेवाओं की प्रशासनिक लागत के संदर्भ में समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उनमें सुधार करना है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग तैयार नहीं करता है। हालांकि, व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) कार्यक्रम के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन निम्नलिखित चार प्रतिशत-आधारित श्रेणियों में निर्दिष्ट सुधार मापदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर किया जाता है:-

1) टॉप अचीवर्स: जो 90% से अधिक स्कोर करते हैं
2) अचीवर्स: जो 80% से 90% के बीच स्कोर करते हैं
3) फास्ट मूवर्स: जो 70% से 80% के बीच स्कोर करते हैं, और
4) एस्पायरर्स: जो 70% से कम स्कोर करते हैं

बीआरएपी 2022 सर्वेक्षण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वाई श्रेणी **(जिसमें स्थापित व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित प्रणालियों वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं)**	
बी2जी **(व्यवसाय केंद्रित सुधार)**	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
फास्ट मूवर्स	गुजरात
एस्पायरर्स	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, झारखंड, राजस्थान, असम, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर
सी2जी **(नागरिक केंद्रित सुधार)**	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

एस्पायरर्स	केरल, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, पंजाब
एक्स श्रेणी {पूर्वोत्तर राज्य (असम को छोड़कर) और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) शामिल हैं}	
बी2जी **(व्यवसाय केंद्रित सुधार)**	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, त्रिपुरा, चंडीगढ़, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पुदुच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश
सी2जी **(नागरिक केंद्रित सुधार)**	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	चंडीगढ़, दमन एवं दीव, मेघालय, अंडमान, त्रिपुरा, पुदुच्चेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर

(ग) और (घ): विश्व बैंक समूह ने अब डूईंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया है और अब दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के व्यवसाय और निवेश परिवेश का आकलन करने के लिए बिजनेस रेडी (बी-रेडी) नामक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग परियोजना तैयार की गई है। बी-रेडी का उद्देश्य विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के विकास के लिए व्यवसायिक परिवेश में सुधार करना है। भारत सरकार व्यवसायों पर विनियामक बोझ को कम करने के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पहल पर लगातार काम कर रही है जो बी-रेडी परियोजना के अनुरूप भी है।

*****